P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-1) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

स्वर्ण जयन्ती ग्राम्य स्वरोजगार योजना की पुर्नसंरचना विशेष रूप से एन0आर0एल0एम0 के सम्बन्ध में

राजेश कुमार गंगवार
शोधार्थी,
बेसिक शिक्षा विभाग,
पू0 मा0 वि0 सिसनई वि0 क्षे0 ददरौल, शाहजहाँपुर

सारांश

बढ़ती हुई बेरोजगारी और निर्धनता विकासशील देशों की ज्वलन्त समस्या है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को समझते हुये ग्रामीण रोजगार और समृद्वि को बढ़ाने के लिये स्वर्ण जयन्ती ग्राम्य स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की। इस योजना से ग्रामीण जन सुमदाय को काफी अपेक्षाएं थी किन्तु यह योजना अपेक्षानुसार ग्रामीण रोजगार में वृद्वि नहीं कर सकी। जिसके कारण से केन्द्र सरकार ने नई योजना एन0आर0एल0एम0 योजना की शुरूआत की। जो आशा की एक किरण के रूप में प्रस्फुटित हुई। एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्यों में रहा। इस योजना में शोध प्रक्रिया के अन्तर्गत समूह बनाकर इच्छुक व्यक्तियों को लाभान्वित कर उन्हें स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया गया। योजना की प्रमुख समस्याओं में मात्र सब्सिडी हासिल करने तक ही समूह क्रियान्वित करना रहा है। निष्क्रिय सदस्यों को समय–समय पर प्रोत्साहन करना आवश्यक होगा। इस मिशन के अन्तर्गत बेरोजगारी को दूर करने के साथ–साथ कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, असमानता के वितरण को समाप्त करना, लिंगीकरण के भेदभाव को समाप्त करना एवं कौशल विकास का निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसी प्रत्याशा की जाती है कि भविष्य में यही योजना अन्य योजनाओं के लिये प्रभावी रोल मॉडल के रूप में कार्य करेगी एवं वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

मुख्य शब्द : एन0आर0एल0एम0, स्वालम्बी विपणन एवं संरचना, कौशल विकास।

प्रस्तावना

एस0आर0 हाशिम की समिति की अनुशंसा के आधार पर 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम्य स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया जिसमें पूर्व में संचालित योजनाओं को (ट्राईसेम, सिद्वा, डी0डब्लू0सी0आर0ए0, जे0के0वाईएम0डब्लू0एस0) सम्मिलित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न घटकों तथा निर्धनों के लिये क्षमता निर्माण, ऋण उपलब्धता, प्रौद्योगिकी अंतरण/उन्नयन, विपणन एवं अवसंरचना के बीच बेहतर ताल मेल स्थापित करना आदि उद्देश्य रहे, परन्तु वास्तव में जो प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं मिली जैसे– विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूह का असमान गठन, लाभार्थियों की कम क्षमता, कम ऋण उपलब्धता तथा व्यवसायिक कौशल विकास की कमी रही। जिस कारण से एक नई योजना का निर्माण किये जाने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें उक्त कमियों को दूर करके गरीबी का उन्मूलन करने में सहायक हो।

एस0जी0एस0वाई की 2 जून 2011 में नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन (NRLM) के रूप में प्रो0 राधाकृष्णा समिति के आधार पर पुर्नसंरचना की गयी। (NRLM) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित गरीबी निवारण से सम्बन्धित योजना है। (NRLM) के द्वारा गरीब परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार तथा कौशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा तब तक सहायता पहुँचाना एवं पोषण करना है, जब तक कि उनकी निर्धनता दूर नहीं हो जाती है। (NRLM) योजना के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु यह रहा कि गरीब लोगों को स्वावलम्बी बनाया जा रहा है तथा समूह बनने से सामाजिक जुड़ाव भी एक बिन्दु के रूप में रहा है। (NRLM) यह मानता है कि इस प्रक्रिया का सबसे अच्छे ढंग से प्रबन्धन और स्वामित्व परिवर्तित एवं अधिकार सम्पन्न महिलाओं द्वारा किया जाता है, न कि मिशन या गैर–सरकारी संगठनों जैसे बाह्य एजेन्टो द्वारा। बाह्य

एजेन्टो की मुख्य भूमिका केवल इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तथा समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इस प्रक्रिया का जिम्मा लेने के लिये सक्षम बनाने की है। इस प्रकार यह मिशन सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है न कि 'कार्यान्वयनकर्ता' की। (NRLM) भारत के सभी 29 राज्यों एवं 5 संघ राज्यों के 6,40,000 गॉवों, 2,38,000 ग्राम पंचायतों, 5852 ब्लाकों और 649 जिलों को कवर किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. निर्धनता उन्मूलन में एन0आर0एल0एम0 की भूमिका का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के सुदृढ़ीकरण के लिये क्षमता और विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
3. पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये आवश्यक सभी कार्यकलाप करना ताकि वे संस्थाएं राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन से सम्बन्धित अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
4. ताल मेल माध्यम से गरीबी उपशमन की भागीदारी पूर्ण सूक्ष्म स्तरीय आयोजन को बढ़ावा देना।
5. रोजगार से सम्बद्ध कौशल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्य सरकारों को व्यवसायिक सहायता प्रदान करना।
6. भारत सरकार और राज्य सरकारों के अन्य कार्यक्रमों/स्कीमों के साथ एन0आर0एल0एम0 के कार्यकलापों के तालमेल के सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
7. महिला सशक्तिरण को बढावा देना।

शोध प्रविधि एवं प्रक्रिया

एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को समूह में रखा जाता है तथा समूह की एकता के साथ–साथ अपने कार्य को सम्पादित करना होता है। ये समूह ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 भी हो सकता है तथा साथ ही पुरूष महिला समूह भी बनाये जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्तियों को लाभान्वित कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किये जाने का प्रयास किया जाता है।

प्रमुख समस्यायें

1. बैंकों द्वारा समूहों को प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया जाता है तथा ऋण की वसूली में ढील भी नहीं दी जाती है। जिससे व्यक्तियों में अपने कार्य के प्रति उत्साह नहीं रह जाता।
2. समूह में कुछ व्यक्तियों का सक्रिय न होना।
3. समूह के सदस्यों का लालच में आ जाना तथा मात्र रिवाल्विंग फण्ड हासिल करने तक की सीमित रहना।
4. मात्र सब्सिडी हासिल करने तक ही समूह क्रियान्वित करना।

समस्या समाधान के सुझाव

1. समूहों को वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देना।
2. समूहों को ठीक ढंग से कार्य करने के लिये जनपद स्तर पर एक मानीटरिंग समिति का होना।
3. समूहों के कुछ सदस्यों को निष्क्रिय हो जाते हैं उन्हें सक्रिय बनाये रखने के लिये प्रोत्साहित करना।
4. समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री को न बिक पाने की स्थिति में सरकार द्वारा स्वयं खरीदना।

निष्कर्ष

एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना जिससे सर्वाधिक अभावग्रस्त समुदाय अर्थात मानव मल–मूत्र ढोने वाले व्यक्तियों, मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों, विशेष रूप से अभावग्रस्त जनजातीय समूहों, विकलांग व्यक्तियों और बंधुओं मजदूरी पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिससे ऐसे समूहों के लोगों को गरीबी से उबारने में मदद मिल सके।

इस योजना में विशेष रूप से नारी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। जिससे कि लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके। क्योंकि लैंगिक भेदभाव आज देश की विकराल समस्याओं में से एक है। यह मिशन वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय करते हुये सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित वित्तीय प्रौद्योगिकी बैंक मित्र जैसे सामुदायिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा इसके तहत विशेष रूप से स्थानीय प्रवसन वाले क्षेत्रों में धन प्रेषण की व्यवस्था की जाती है।

आजीविका मिशन में कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में नये अवसर उपलब्ध उत्पन्न करते हुये कौशल निर्माण एवं स्व–नियोजित व्यक्तियों एवं उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के जरिये और उन्हें प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया गया है। इस मिशन की पहल बेरोजगारी दूर करने के साथ–साथ कल्याणकारी समाज की स्थापना करना एवं महिला शक्ति को बढ़ावा देना एवं लिंगीकरण के भेदभाव को समाप्त करना, असमानता के वितरण को समाप्त करना, निश्चित रूप से यह परिकल्पना की जाती है कि यह परियोजना आगे बढ़ाये जाने योग्य उच्च स्तरीय मॉडलों और संसाधन केन्द्रों के रूप में उभरकर सामने आयेगी और देश के लिये सुदृढ़ रोल मॉडल का रास्ता तैयार करेगी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

इकोनॉमी सर्वे 2012–13
सर्वेक्षण तथा विश्लेषण (भारतीय अर्थव्यवस्था) 2018 प्रो0 एस0एन0 लाल, डा0 एस0के0 लाल
एन0आर0एल0एम0 स्वरोजगार योजना की अवधारण एक नजर में एन0आर0एल0एम0 बेबसाइट 2019
आयोजन एवं विकास 2016 (एम0एल0 झींगन)
भारतीय अर्थव्यवस्था (2018–19 परीक्षा वाणी)
अतिरिक्तांक (2014–15 प्रतियोगिता दर्पण)